

पहले मुख्य समाचार।

- एक दिवसीय दौरे पर आज मेरठ आ रहे हैं उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। नारी शक्ति महोत्सव में शामिल होने के साथ कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण।
- अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना भी सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान बेच सकेंगे गेहू। प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश।
- सरकार ने चौबीस और आईएस अधिकारियों के किए तबादले। दस जिलों के जिलाधिकारी बदले गए।

उप राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन आज मेरठ में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान लगभग तीन हजार सात सौ विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद अरुण गोविल भी उपस्थित रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मंत्री अट्टाज्ञास अप्रैल को वाराणसी आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर बरेका परिसर में नारी शक्ति महोत्सव आयोजन में शामिल होंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी दोपहर बाद 28 अप्रैल को काशी में आएंगे और हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ हमारे काशी की लगभग 50 हजार से ज्यादा हमारी बहनें इकट्ठा होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी। मातृशक्ति के लिए आत्मनिर्भर, स्वावलंबन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में सहभागिता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमारी मातृशक्ति उपस्थित होकर के संवाद के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करेंगी।

उन्तीस अप्रैल को प्रधानमंत्री हरदोई में प्रस्तावित कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्से से जोड़ने का काम करेगा।

प्रदेश सरकार ने तीस अप्रैल को विधान मंडल का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बार्ड सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार ने यह प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया है। राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुपत योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कल कहा कि इस याचिका को इसी तरह के मुद्दों पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा जाएगा। याचिका में कहा गया है कि सरकारें इन योजनाओं के लिए लगातार कर्ज ले रही हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर है और वितरकों में किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कल यह जानकारी दी।

वेस्ट-एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई इफेक्ट हुई है और सरकार ने इफेक्टिव मेनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरिया में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना।

प्रदेश के किसान अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी अपने गेहू को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय कल तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को इस

आदेश का तुरंत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसान पहले की तरह सुगमता से अपनी उपज बेच सकें। गेहूं खरीद का मौजूदा सत्र मार्च के अंत से मध्य जून दो हजार छब्बीस तक चल रहा है। इससे पहले ऑनलाइन पोर्टल या यूपी किसान मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य था, जिससे कुछ किसानों को परेशानी हो रही थी। अब इस बाधा को हटा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकें।

प्रदेश सरकार ने कल दस जिलों के जिलाधिकारियों सहित चौबीस आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार अलीगढ़, एटा, बांदा, फर्रुखाबाद, हापुड़, अंबेडकरनगर, सोनभद्र, गाजीपुर, अयोध्या और बाराबंकी के जिलाधिकारी बदल दिये गये हैं। इससे पहले, उन्नीस अप्रैल की देर रात सरकार द्वारा पंद्रह जिलों के जिलाधिकारियों सहित चालीस आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया।

प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच हुए एमओयू के तहत ऑस्ट्रेलिया से विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में सीएम मॉडल स्कूल का भ्रमण किया और शिक्षा व्यवस्था का जमीनी स्तर पर अवलोकन किया। इसके साथ जनपद के चयनित शिक्षकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग पचीस शिक्षकों ने भाग लिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले वर्ष हुए एमओयू के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम 'योगी की पाती' जारी कर मौसम में हुए बदलावों के प्रभावों के प्रति लोगों को सतर्क किया। एक रिपोर्ट—

एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये 'योगी की पाती' जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ता तापमान इसके दुष्प्रभावों से बचने तथा अपनी तैयारियां पूरी करने का संदेश दे रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कड़कड़ाती ठंड की तरह प्रचंड गर्मी की मार से बचाने की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए शासन के हर स्तर पर समन्वित और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घर के बाहर पशु-पक्षियों के लिए पानी रखें। बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनें। साथ ही ऐसी कोई भी लापरवाही न करें, जिससे आग लगने का अंदेश हो। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बीते चौबीस घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिजली की बढ़ी हुई मांग के अनुसार आपूर्ति के निर्देश दिये हैं। एक रिपोर्ट—

भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप लगभग 34,00 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी थर्मल पावर प्लांट को पूरी क्षमता से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हीट स्ट्रोक से प्रभावितों के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर के प्राणि उद्यानों में भी हीट-वेव एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने का यलो अलर्ट जारी किया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालय में पठन-पाठन के समय में बदलाव किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थी सुबह साढ़े सात बजे से अपराह्न साढ़े बारह बजे तक उपस्थित रहेंगे। शिक्षकों और विद्यालय के सभी कर्मियों को सुबह साढ़े सात बजे से अपराह्न डेढ़ बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
